

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—88/2010/223 (2010/00007)

1. बिरदा पुत्र चीमा रावत (मृतक) के उत्तराधिकारीगण:—
1/1— रामा पुत्र बिरदा,
1/2— बोदू पुत्र बिरदा,
दोनों जाति रावत, नि० ग्राम धोलादांता न्यांरा, तह० नसीराबाद, जिला अजमेर ।
1/3— लाली पुत्री बिरदा पत्नी सुवालाल, नि० आव, भिनाय, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
2. किशना पुत्र छोगा रावत, निवासी ग्राम धोलादांता, तह० नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मंगला पुत्र नाथा रावत (मृतक) वारिस:—
1/1— सोहन पुत्र मंगला,
2. लाडू पुत्र नाथा रावत (मृतक) वारिस:—
2/1— जेटू पुत्र लाडू
2/2— कल्याण पु लाडू
2/3— गोपाल पुत्र लाडू
3. गोकुल पुत्र बीजा,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम धोलादांता न्यास, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 16.3.2010 अंतर्गत वाद संख्या 17/1994 .

उपस्थित:—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गौतम टांक, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3.

निर्णय

दिनांक:— 28.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2010 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 188, 183, 92—ए राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम न्यारा के खसरा नंबर 1815/1 रकबा 1 बीघा किस्म बरड़ा की आराजी दिनांक 28.8.1975 को अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर ने वाद संख्या 390/75 के निर्णय में वादी के पक्ष में छोटी पट्टी के रूप में नियमन की थी । नियमन दिनांक के 15 वर्षों से पूर्व ही वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । नियमन के आधार पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतरण दर्ज किया गया । प्रतिवादीगण ने दिनांक 1.2.1994 को उक्त आराजी पर 10 फीट लंबी व 10 फीट चौड़ी नींव कमरा निर्माण की गरज से खोद

ली है । अतः प्रतिवादीगण को बेदखल कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी०न्याया० ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2010 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया । रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम न्यारा के खसरा नंबर 1815/1 रकबा 1 बीघा किस्म बरडा की आराजी दिनांक 28.8.1975 को अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर ने वाद संख्या 390/75 के निर्णय में वादी के पक्ष में छोटी पट्टी के रूप में नियमन की थी । नियमन दिनांक के 15 वर्षों से पूर्व ही वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । नियमन के आधार पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतरण दर्ज किया गया था। अधी०न्याया० के समक्ष वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श-1 आवंटन आदेश, प्रदर्श-2 वर्किंग जमाबंदी प्रस्तुत की तथा अपने बयान लेखबद्ध कराये थे जिसमें कथन किया था वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1815/1 रकबा 1 बीघा वादीगण की खातेदारी भूमि है तथा पड़ौस में प्रतिवादीगण ने सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और उनकी बाउण्ड्री पर चार दीवारी बनाने के लिये जबरदस्ती व बलपूर्वक दिनांक 20.3.2006 को 5 फीट ऊंची दीवार के रूप अवैध रूप से कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने प्रथम तनकी का निर्णय इस आधार पर किया है कि नियमन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियमन का अधिकार न्यायालय को नहीं है तथा दिनांक 5.12.1978 को नामांतरण से अस्वीकृत कर दिया गया को चुनौती नहीं दी गई है और किस आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादीगण के नाम दर्ज की गई को स्पष्ट नहीं किया गया तथा कब्जा होने का कथन करते हैं किन्तु धारा 91 के नोटिस व खसरा गिरदावरियों पेश नहीं की है जबकि प्रतिवादगण ने धारा 91 के नोटिस पेश किये हैं । इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण ने अधी०न्याया० के समक्ष प्रदर्श-1 नियमन आदेश की प्रति पेश की तथा वादीगण के निरन्तर कब्जा काश्त होने से गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई तथा गैर खातेदारी से खातेदार वर्किंग जमाबंदी में दर्ज की गई किन्तु अधी०न्याया० ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 [वादीगण/अपीलांटस](#) के विरुद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 3 का भी निर्णय गलत किया है क्योंकि वादीगण को विवादित आराजियात नियमन की गई थी जिसके वे खातेदार काश्तकार हैं जिनके कब्जे काश्त में किसी अन्य द्वारा दखलदांजी किये जाने पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं किन्तु अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 1 में दिये गये निष्कर्षों के आधार पर तनकी संख्या 3 का निर्णय अपीलांटस के विरुद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर [वादीगण/अपीलांटस](#) का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा [वादीगण/अपीलांटस](#) द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पों 1 लगायत 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपीलान्टस निरस्त की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी०न्याया० ने वाद को निर्णित करने हेतु पांच तनकियात कायम की है । अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 1 इस आधार पर वादीगण के विरुद्ध निर्णित की है कि नामांतरण संख्या 89 उक्त नियमन आदेश की पालना हेतु दर्ज किया गया था किन्तु दिनांक 5.12.1978 को अति० तहसीलदार व सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, अजमेर ने कैम्प न्यारा में उक्त नामांतरण को अस्वीकृत कर दिया था । वादीगण ने उक्त अस्वीकृत नामांतरण को कभी भी चुनौती नहीं दी है इसके बावजूद किस आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज की गई यह वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है । हम अधी०न्याया० के तनकी संख्या 1 के संबंध में पारित निर्णय से सहमत है क्योंकि नियमन आदेश की पालना में नामांतरण अस्वीकृत होने के बाद अस्वीकृत नामांतरण को चुनौती दिये बिना विवादित भूमि किस आधार पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई स्पष्ट नहीं किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में खसरा गिरदावरियों, धारा 91 के नोटिस इत्यादि साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात पर अपीलान्टस/वादीगण का कब्जा काश्त रहा हो । वादीगण स्वयं ने अपने वाद पत्र में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है जिससे वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना भी नहीं माना जा सकता है । अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्टस खारिज योग्य तथा अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।
7. अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2010 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर